ASIAN AMERICANS ADVANCING JUSTICE AAJC

2020 जनगणना मुकदमेबाज़ी और एशियाई अमरीकी समुदायों के लिए इसका क्या अर्थ है

अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रशासन को 2020 की जनगणना में नागरिकता का प्रश्न शामिल करने से रोकने के बाद, प्रशासन ने 2020 की जनगणना को कमज़ोर करने के लिए और पूर्व समय में कम गिने गए समुदायों को हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में पूर्ण और सटीक रूप से गिने जाने और प्रतिनिधित्व किए जाने से रोकने के लिए अन्य ढंगों का उपयोग किया। www.CountUsIn2020.org पर 2020 की जनगणना और इस बारे में अधिक जानें कि यह हमारे समुदायों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है।

प्रमुख निष्कर्ष:

1. संविधान के अनुसार, जनगणना में प्रत्येक व्यक्ति को गिना जाना चाहिए। इमीग्रेशन स्टेटस पर ध्यान न देकर, हमारे समुदायों के प्रत्येक व्यक्ति को शामिल किया जाना चाहिए।
2. जनगणना हमारे समुदायों को प्राप्त होने वाले संघीय धन और संसाधनों और अगले दस वर्षों के लिए हमारे राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आवाज़ को प्रभावित करती है। संसाधनों में हमारी उचित हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए हमें एक पूर्ण और सटीक गणना की आवश्यकता है।
3. अब जब 2020 की जनगणना की गिनती सामप्त हो गई है, तो जनगणना ब्यूरो के पास उसके द्वारा एकत्र किए गए डेटा पर प्रक्रिया करने और किसी भी त्रुटि की पहचान करने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए। 31 दिसंबर तक अंतिम संख्याओं की रिपोर्ट करने के लिए डेटा प्रक्रिया में तेज़ी करने से संभावित रूप से पूर्व समय में कम गिने गए समुदायों की गलत गिनती होगी।

2020 की जनगणना के संबंध में चल रहे मुकदमों में क्या दांव पर लगा है?

- पूर्ण और सटीक जनगणना के लिए निरंतर लड़ाई में अदालतों में कई मुकदमें किए जा रहे हैं। मुकदमेबाज़ी के तीन प्रमुख मुद्दे निम्न हैं: (1) गिनती और डेटा प्रक्रिया की छंटाई; (2) कांग्रेस के नियुक्तिकरण से बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासियों को बाहर करने के लिए राष्ट्रपति का पत्रक; और (3) राज्य-व्यवस्थीकरण प्रक्रिया से गैर-अमरीकी नागरिकों को बाहर करने के लिए एक डेटा फाइल (जिसे नागरिक मतदान आयु जनसंख्या या "CVAP" फाइल कहा जाता है) का निर्माण। एशियाई अमरीकी उन्नत न्याय | AAJC ("उन्नत न्याय-AAJC"), MALDEF (मैक्सिकन अमरीकी कानून रक्षा और शैक्षिक निधि) के सहित, वर्तमान में संघीय अदालत में जनगणना को कमज़ोर करने के इन प्रयासों को चुनौती दे रहे हैं।
- ***समयरेखा की छंटाई:*** जब कोविड-19 महामारी के कारण जनगणना ब्यूरो अपनी संचालन योजना को बदलने के लिए मजबूर थी, तो जनगणना ब्यूरो ने निर्धारित किया कि एक पूर्ण और सटीक

गणना सुनिश्चित करने के लिए इसे 31 अक्टूबर, 2020 तक गिनती जारी रखने की आवश्यकता है और 30 अप्रैल, 2021 तक डेटा पर प्रक्रिया करना जारी रखने की आवश्यकता है। हालांकि, अगस्त में, जनगणना ब्यूरो ने अचानक घोषणा की कि वह 30 सितंबर, 2020 को गिनती को समाप्त करके जनगणना करने के लिए आवश्यक समय में कटौती करेगा और 31 दिसंबर, 2020 तक डेटा की प्रक्रिया करेगा और राष्ट्रपति को अंतिम गणना की रिपोर्ट करेगा।

- ***राष्ट्रपति का प्रपत्र:*** इमीग्रेशन स्टेटस पर ध्यान न देकर, प्रत्येक व्यक्ति को दशवार्षिक जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि, 21 जुलाई, 2020 को, राष्ट्रपति ट्रम्प ने राज्यों के बीच कांग्रेस की सीटों को आवंटित करने के लिए उपयोग की जाने वाली जनगणना की गिनती से बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासियों को बाहर करने के लिए एक प्रपत्र जारी किया। संविधान में कहा गया है कि कांग्रेस की सीटों को "प्रत्येक राज्य में व्यक्तियों की पूर्ण संख्या" के आधार पर आवंटित किया जाना चाहिए ताकि राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाए। नियुक्तिकरण गिनती से बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासियों को हटाना अभूतपूर्व और असंवैधानिक है और इससे बड़ी संख्या में प्रवासी समुदायों वाले स्थानों से राजनीतिक प्रतिनिधित्व दूर हो जाएगा।
- ***CVAP फाइल***: जुलाई 2019 में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकता के प्रश्न को शामिल करने से रोकने के कुछ ही दिनों बाद, राष्ट्रपति ट्रम्प ने एक कार्यकारी आदेश जारी किया, जिसमें जनगणना ब्यूरो को संघीय और राज्य एजेंसियों से नागरिकता डेटा एकत्र करने का निर्देश दिया गया था, ताकि राज्य गैर-अमरीकी नागरिकों को जनसंख्या की गणना से बाहर कर सकें जिसका उपयोग राज्य के वैधानिक ज़िलों के लिए किया जाता है। ब्लॉक स्तर पर केवल नागरिकता वाले डेटा के साथ CVAP फाइल का उपयोग करने से प्रवासी समुदायों में रह रहे लतीनियों और एशियाई अमेरीकियों की राजनीतिक शक्ति में ग़ैर-अनुपाती ढंग से कमी आएगी।

मौज़ूदा भूदृश्य क्या है?[1]

- 2020 की जनगणना के लिए गिनती 15 अक्टूबर, 2020 को समाप्त हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने तब गणना की छंटाई कर दी जब उसने निचली अदालत के एक आदेश पर रोक लगा दी थी जिसने जनगणना ब्यूरो को 31 अक्टूबर तक गिनती जारी रखने का निर्देश दिया था, जैसी कि जनगणना ब्यूरो ने मूल रूप से कोविड-19 महामारी के बाद से योजना बनाई थी।

[1] पिछली बार 26 अक्टूबर, 2020 को अपडेट किया गया। जैसे-जैसे मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ेगी, ज़मीनी हकीकत पर परिस्थितियों में परिवर्तन होगा।

- अब जब गणना समाप्त हो गई है, जनगणना ब्यूरो को अपने द्वारा एकत्र किए गए डेटा पर प्रक्रिया करनी होगी और रिपोर्टिंग के लिए संख्याओं को तैयार करना होगा। यह “डेटा संग्रह के बाद की प्रक्रिया” किसी भी त्रुटि की पहचान करने और एक सटीक गणना सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- जनगणना ब्यूरो के लिए राष्ट्रपति को अंतिम 2020 की गिनती प्रस्तुत करने की वर्तमान समय सीमा 31 दिसंबर, 2020 है। हालांकि, जनगणना ब्यूरो ने पहले भी बार-बार कहा है कि इस समय सीमा को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, और यह सुनिश्चित करने के लिए उन्हें 30 अप्रैल 2021 तक का समय चाहिए कि वह सभी आवश्यक डेटा प्रक्रिया के चरणों का संचालन कर सके।
- कई मुकदमों में आग्रह किया गया है कि 31 दिसंबर की समय सीमा को रद्द किया जाना चाहिए। कैलिफोर्निया में एक संघीय न्यायाधीश ने सहमति व्यक्त की और रिपोर्टिंग के लिए 30 अप्रैल, 2021 की समय सीमा को बहाल किया। सरकार ने उस निर्णय की अपील की, और निर्णय को अपील पर रखे जाने के साथ फैसले पर रोक लगाई हुई है। इसका अर्थ यह है कि फिलहाल, जनगणना ब्यूरो को 31 दिसंबर, 2020 तक नियुक्तिकरण गणना की रिपोर्ट करने और उनकी योजना के विपरीत पोस्ट-प्रोसेसिंग को संचालित करने के कार्य को आधे से भी कम समय में करने का काम सौंपा गया है।
- बात रही राष्ट्रपति के मेमो की, तो 10 सितंबर, 2020 को, न्यूयॉर्क में तीन संघीय न्यायाधीशों के एक पैनल ने फैसला सुनाया कि बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासियों को कांग्रेस की नियुक्तिकरण गणना से बाहर करना गैरकानूनी था। ट्रम्प प्रशासन ने इस फैसले की अपील की है, और सर्वोच्च न्यायालय 30 नवंबर को इस मामले की सुनवाई करने वाला है।

एशियाई अमरीकी, मूल हवाई निवासियों और प्रशांत द्वीप समूह समुदायों के लिए इसका क्या अर्थ है?

- आज, मोटे तौर पर पाँच में से एक एशियाई अमरीकी और तीन मूल हवाई निवासी और प्रशांत द्वीप समूह के निवासी ऐसे पड़ोस में रहते हैं जहाँ गणना करना मुश्किल है और जिनकी पूर्व समय में जनगणना में कम गिनती की गई है। अगले दस वर्षों के लिए स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा से लेकर आवास और परिवहन तक सभी चीज़ों के लिए एक पूर्ण और सटीक गणना की आवश्यकता है।
- भले ही जनगणना की गिनती बंद हो गई है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए हमारे प्रयास समाप्त नहीं हुए हैं कि हमारे समुदायों का जनगणना में पूरी तरह से प्रतिनिधित्व किया जाता है, और इससे होने वाली धन और राजनीतिक शक्ति को सुरक्षित रखा जाता है। 31 दिसंबर तक अंतिम संख्याओं की रिपोर्ट करने के लिए डेटा प्रक्रिया में तेज़ी करने से संभावित रूप से पूर्व समय में कम गिने गए समुदायों की गलत गिनती होगी।

- संविधान में यह स्पष्ट है कि जनगणना में "प्रत्येक राज्य के व्यक्तियों की पूरी संख्या की गणना की जानी चाहिए।" कांग्रेस की सीटों को आवंटित करने की गिनती से हमारे समुदाय के बिना दस्तावेज़ वाले सदस्यों को निकालना प्रवासी समुदायों और रंग के कई समुदायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को ग़ैर-अनुपाती ढंग से प्रभावित करेगा।
- MALDEF के साथ साझेदारी में, उन्नत न्याय-AAJC हमारे समुदायों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए अदालत में इन मुद्दों पर लड़ना जारी रखता है।